

cp. 90

न्यायग्रलय श्रीमान राजस्व मंडल गवालियर मो प्र०

8

R-2757-11114

श्रीमति आशा पत्नी श्री प्रकाश अहिह्वार उम्र 45
वर्ष निवासी रौरईया चौराहा टीकमगढ़ म, प्र,

..... निगराकार

બનામ

प्रकाश तनय श्रीमद्भूषण श्रीशाम अग्रवाल निवासी नूतन
विहार कालोनी दौगा टीकमगढ़ तहसील जिला
टीकमगढ़ म० प्र०

.....प्रतिनिगराकार

आवैदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा.संहिता

महोदय.

निगराकार सादर निम्न प्रकार विनयी है :-

११४ यह कि निगराकार ने भू. ख. क्र. 463 रकवा ०.३७६ आरे दिनांक ३०.६.२००० को विक्रेताम्बासर्कार शिला अहिरवार, किस्मु अहिरवार, अन्तुआ अहिरवार निवासी ग्राम नयाखेरा तह.व जिला टीकमगढ म० प्र० से क्रय की थी तथा रजिस्ट्री दिनांक को ही कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा सङ्क किनारे की रजिस्ट्री हुई थी । तथा उसी समय छछ निगराकार ने कथित भू. ख. क्र. पर मकान निर्माण कर लिया था तथा फैन्सिंग कर कब्जा कर लिया था । तथातभी से लगाता -र कथित भू. ख. क्र. 463 पर स्वत्व स्वामित्व एवं एवं कब्जाधारी होकर कृषि कार्य करती चली आ रही है तथा ५०-६० वर्ष पूर्व से विक्रेतागण का बिज रहे है जिस हेतु विक्रेतागणों का शपथ पत्र संलग्न है ।

१२४ यह कि भू. ख.क्र. 455,466 श्रीमति चन्द्रप्रभा यादव निवासी
टीकमगढ़ द्वारा वर्ष 1999 में क्रय की थी। तथा उसके बाद वर्ष 2012 में भू. ख.
क्र. 455,466 प्रतिनिगराकार ने क्रय की है।

४३४ यह कि निगराकार क्रय दिनांक से लगातार अपनी कृषि भूमि पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(8)

प्रकाशन क्रमांक निगरानी 2757-तीन / 2014

जिला-टीकमगढ़

स्थान व दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभि. आदि के
हस्ताक्षर

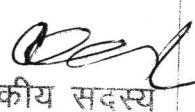
7-1-15

सामग्र कैप

आवेदक अधिवक्ता श्री राजेश सेन उपस्थित है। उन्हें
ग्राहयता पर सुना।

2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार
किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील
न्यायालय टीकमगढ़ के प्रक. 83/अ-12/12-13 में पारित आदेश
दिनांक 12-6-14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया,
जिसके विरुद्ध में आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के
समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— राजस्व निरीक्षक टीकमगढ़ के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट
है कि उनके द्वारा सीमांकन प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का पालन
करते हुये सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की गई है जिसमें कोई त्रुटि
परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रथमदृष्ट्या यह निगरानी विधिसंगत
नहीं होने से इसी स्तर पर पर अग्राह्य की जाती है।


प्रशासकीय सदस्य